1

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS M N 06 SEP 2023 No. 3 RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2086)

Name of Candidate	Neeraj Dhakad		
Medium Eng./Hindi	hindi	Registration Number	1177040
Center	M.N.	Date	06/09/2023

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH.**
   इसमें बीस प्रश्न हैं **हिन्दी और अंग्रेजी** में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended	Strongly Recommended

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

2086

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है?

Do you agree with the view that there is a need to enact a new law for ensuring judicial accountability in India? (Answer in 150 words) 10

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) एवं 217 में न्यायिक नियुक्तियों का वर्णन है लेकिन व्यवहार में न्यायिक नियुक्तियाँ कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती हैं। जिसमें न्यायिक सदस्य ही शामिल होते हैं।

न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्यों है -

① 'ऑटोक्रेटिक' की मौजूदगी को समाप्त करने के लिये
↳ जहां न्यायिक नियुक्तियां स्वयं के द्वारा होती हैं

② शक्ति के पृथक्करण को सुनिश्चित
↳ न्यायपालिका - कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के लिये (Article - 50)

③ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये
↳ नियुक्तियों एवं स्थानांतरण में पारदर्शिता नहीं

④ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिये
↳ लोगों को निष्पक्ष न्याय मिल सके

⑤ न्यायिक अतिसक्रियता पर नियंत्रण के लिये

2086
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

नये कानून के माध्यम से

- न्यायिक संयम की प्राप्ति
  - अलमित्रा एच. पटेल वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक संयम को अपनाने पर बल
- कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप से बचा जा सकेगा।
- निष्पक्ष न्याय को बल मिलेगा
- लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा
- न्यायिक जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी
- न्यायपालिका पर आरोप-प्रत्यारोप की समाप्ति। जैसे NJAC को असंवैधानिक घोषित करने पर आरोप लगा
- उचित आलोचना संभव हो सकेगी।

निष्कर्षतः न्यायपालिका में सुधार एवं जवाबदेहिता के माध्यम से त्वरित न्याय एवं पितृसत्तात्मक न्याय की प्राप्ति की जा सकती है।

2086

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) में संवैधानिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य रहा है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए।

Constitutionally reconciling Fundamental Rights with the Directive Principles of State Policy (DPSPs) has been a tough task since the inception of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

मिनर्वा मिल्स वाद में मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSPs) में एकता का संबंध बताया है और इसे आधारभूत ढाँचे का भाग बताया है।

मूल अधिकार एवं DPSPs के बीच सामंजस्य कठिन कार्य कैसे -

① मूल अधिकार वादयोग्य हैं जबकि DPSPs वादयोग्य नहीं हैं
जैसे शंकरी प्रसाद वाद में भूमि सुधारों (DPSPs) एवं संपत्ति के अधिकार (अनु. 19(1)(f) एवं 31 में टकराव

② नीति निदेशक तत्वों की प्राप्ति सरकार के लिये महत्व रखती है तो वहीं इसकी टकराहट मूल अधिकारों से भाग से हुई
केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य में भूमि सुधारों एवं अनु. 14, 19, 31 के बीच टकराहट में अनुच्छेद 39 (b) एवं 39 (c) को वरीयता दी गई।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) अनुच्छेद 46 को बढ़ावा देने के लिये मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 एवं 15 के बीच टकराहट हुई

(4) सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से DPSP की स्थापना के चलते मूल अधिकार 13(2) न्यायिक समीक्षा के साथ टकराहट हुई

(5) अनुच्छेद 44 (यूनिफॉर्म सिविल कोड) एवं अनुच्छेद 25-28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बीच टकराहट का मामला

(6) सामंजस्य कमी के रूप में शायरा बानो मामले में तीन तलाक का मामला महिलाओं को वरित सुनवाई का अधिकार (DPSP) एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से टकराहट।

निष्कर्षतः कुछ विरोध के बिंदुओं के साथ सामंजस्य के बिंदुओं को भी देखा जा सकता है जहां निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से 21 में शामिल किया, अतः सामंजस्य के बिंदुओं के माध्यम से लोकतांत्रिक उपलब्धियों को बढ़ाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्यों और भारत में नीति-निर्माण को आकार देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the functions performed by the Prime Minister's Office (PMO) and its role in shaping policy-making in India. (Answer in 150 words) 10

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है जो कार्यपालिका एवं प्रशासनिक मशीनरी में समन्वय को बढ़ावा देती है।

PMO के कार्य

- महत्वपूर्ण कार्यपालिका के निर्णय लिये जाते हैं
- बैठकों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका
- किचन कैबिनेट के साथ सिविल सेवकों के साथ संवाद
- नीति-निर्माण को अंतिम रूप दिया जाता है
- योजना के क्रियान्वयन एवं निर्माण की रूपरेखा को बनाया जाता है
- भारतीय वैदेशिक नीति को भी अहम मार्ग प्रदान करता है।

नीति निर्माण को आकार देने में

- नीति-निर्माण में नीति आयोग की भूमिका शामिल
- नीतियों में सार्वजनिक रूप से लोगों के इनपुट को लिया जा सकता है
- गैर-कार्यपालिका से बेहद व्यक्ति का आगमन
- विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है
- न्यायिक उच्च भूमिका न्यायिक निर्णयों को सहकारी बनाया जाता है
- बॉटम-अप अप्रोच के क्रियान्वयन को अंतिम रूप दिया जाता है
- जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर नियम-विनियमन

PMO सहकारी संघवाद एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने और उन पर पुनर्विचार करने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

Re-examination and reconsideration of the provisions of Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) requires striking a balance between concerns of civil liberties and human rights, and maintaining and protecting the sovereignty and integrity of India. Comment. (Answer in 150 words) 10

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A देशद्रोह को परिभाषित करती है जिसमें आघात लिखित रूप में, विचारों के माध्यम से देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता हो शामिल है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में IPC की धारा 124A को पुनर्विचार एवं संशोधन के बारे में कहा है

नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार संबंधी चिंतायें -

- मूल अधिकार जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन (अनुच्छेद-21)
- निवारक नजरबंदी को बढ़ावा देता है (अनु. 22)
- बोलने की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है (अनु.-19)

- आलोचना एवं तार्किक वाद-विवाद पर प्रतिबंध
- लोकतांत्रिक की मूल भावना के विरुद्ध है

भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और उसकी रक्षा

- सुप्रीम कोर्ट ने IPC 124(A) का उपयोग भारत की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रयोग करने की बात कही
- इसके सजा के अन्तर्गत प्रावधान को बढ़ाकर 7 वर्ष करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
- भारत अलगाववाद एवं आतंकवाद से अपनी सीमाओं पर सुभेद्य है अतः IPC 124(A) को बनाये रखना आवश्यक हो जाता है
- राष्ट्रीय सुरक्षा के बिना मानवाधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती है।

निष्कर्षतः IPC 124(A) को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये विरोधी विचारधारा को समाप्त करने के लिये नहीं।

5. "ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।" टिप्पणी कीजिए।

"Citizen participation is key to the success of e-governance initiatives in rural India." Comment. (Answer in 150 words) 10

ई-गवर्नेंस से आशय शासन में तकनीक को शामिल करने से है जिसके माध्यम से उसका विकास नागरिक केन्द्रित, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के रूप में होगा (UNDP)

ई-गवर्नेंस की सफलता के लिये नागरिक भागीदारी

- CPGRAMS के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र जिसमें नागरिक भागीदारी को बढ़ावा
- RTI Act, 2005 के माध्यम से नागरिक सहभागिता
- राजस्थान में ई-मित्र → जिसके माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा
- e-NAM को नागरिकों की सुविधा के लिये प्रयोग
- आंध्रप्रदेश में स्पंदन शिकायत निवारण तंत्र जिसके माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी
- e-भाषिनी के माध्यम से भाषाओं की अभिव्यक्ति

अपितु अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में
↳ लोगों की भागीदारी बढ़ेगी

- faster (सुप्रीम कोर्ट)
↳ इसके माध्यम से कोर्ट के निर्णय तीव्र गति से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेंगे

- ग्राम स्वराज पोर्टल
↳ इसके माध्यम से पंचायतों की दक्षता में वृद्धि की जा सकेगी

- अन्नवितरण पोर्टल → के माध्यम से PDS का बेहतर क्रियान्वयन

- 'उज्ज्वला' का (स्वागत) शिकायत निवारण तंत्र
↳ पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित

निष्कर्षतः नागरिक सहभागिता समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देगा फलतः 2nd ARC की 12th Report नागरिक केन्द्रित प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. आपके अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपनी शुरूआत के बाद से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल रहा है?

How far do you think the Aspirational District Programme has been able to achieve its objectives since its inception? (Answer in 150 words) 10

नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आंकाक्षी जिला कार्यक्रम की उपलब्धियां

- भौगोलिक दूरियों को कम किया
  - जैसे उत्तर-पूर्व को भारत के अन्य भागों से जोड़ा है

- आर्थिक सशक्तीकरण
  - एक ~~उत्पाद~~ जिला, एक उत्पाद को बढ़ावा
  - G.I. Tag में शाही का हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा दिया गया

- सामाजिक
  - लैंगिक ~~सश~~ सशक्तीकरण को बढ़ावा। जैसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य की शॉल एवं अन्य परिधानों को बढ़ावा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अवसंरचना के विकास में
  - PM ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में
  - PM आवास योजना में महत्वपूर्ण

- नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम द्वारा जिलों के महत्व को उभारा किया और खनिज, उद्योग, स्टार्टअप को जिले में बढ़ावा देने में सहायक की भूमिका निभाई

- पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रत्यास्थता
  - को अपनाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का योगदान

आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर योजना का क्रियान्वयन कर SDG-1 (नो पोवर्टी) को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ।

2086
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. NGO क्षेत्रक को आगे बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

Technology has a crucial role to play in advancing the NGO sector and improving outcomes for beneficiaries. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

NGO (गैर सरकारी संस्था) के रूप में मौजूद होती है जिसमें सामाजिक कल्याण एवं जनहितों के लिये व्यापक सामूहिक रूप से शासन-प्रशासन में भूमिका निभाते हैं।

NGO क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी की भूमिका

(1) NGO क्षेत्रक को आगे बढ़ाने

→ NGO की संगठनात्मक संरचना के विस्तार के लिये - मोबाइल एप का प्रयोग

→ NGO के कार्यक्रमों के विस्तार के लिये
↳ सोशल मीडिया का प्रयोग

→ NGO की उपयोगिता को बढ़ाया
↳ AI एवं IOT का प्रयोग किया जा सकता है

→ सदस्यता ग्रहण के लिये ऑनलाइन पोर्टल एवं प्लेटफॉर्म का उपयोग

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(b) लाभार्थियों के लिए आउटकम

- शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका
  जैसे प्रथम फाउंडेशन की कार्यशैली
- पर्यावरण के क्षेत्र में WWF भी वन्यजीव संरक्षणों को आगे बढ़ावा देता है, इसमें उन्नत संवेदन प्रणाली का प्रयोग
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
  ↳ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वैश्विक रैंकिंग में तकनीकी का प्रयोग
- किसानों के लिए
  ↳ किसान कॉल सेंटर
  ↳ वेस्टिवल सेंसर तकनीक का विकास

NGO सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथ ही इनके माध्यम से संधारणीय विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. तकनीकी और उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश से जुड़े निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

Discuss the implications associated with the entry of foreign educational institutions for technical and higher education in India. (Answer in 150 words) 10

भारत में UGC द्वारा विदेशी शिक्षण संस्थानों को अपने परिसर (केवल ऑफलाइन मोड में) की स्थापना करने की अनुमति दी है।

भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना से लाभ –

1. उच्चतर संस्थान में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि
   - NEP-2020 की 2030 तक 50% GER का लक्ष्य रखा है
2. ज्ञान के पलायन को रोका जा सकेगा
3. भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि
   जैसे – QS वर्ल्ड युनिवर्सिटी Ranking 2022 में भारत की केवल 8 विश्वविद्यालय टॉप 400 में जगह बना पाई
4. तकनीकी एवं पाठ्यक्रम का आदान प्रदान हो सकेगा
5. आर्थिक नुकसान में कमी
   - भारतीय विद्यार्थियों द्वारा विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ

2086

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ

① आर्थिक लाभ को अपने देश ले जा सकते हैं

② फीस अत्याधिक होगी
→ असमानता में वृद्धि

③ भारतीय विश्वविद्यालयों को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी

④ लोकल रिजर्वेशन का अभाव
→ गरीब एवं जनजाति समुदाय के छात्र इससे बाहर हो सकते हैं

⑤ पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान भारतीयों पर थोप सकता है।

निष्कर्षतः विदेशी शिक्षा संस्था अपने साथ नवीन तकनीकियों को साथ लायेंगी जिनके माध्यम से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और SDG-4 (Quality Education) की प्राप्ति में सहायक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच फलता-फूलता संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। परीक्षण कीजिए।

The flourishing relationship between India and countries of Latin America has become a critical element of India's foreign policy. Examine. (Answer in 150 words) 10

भारत और लैटिन अमेरिका के देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान से जुड़े हुये हैं जो आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंध

- दोनों ही देश विकासशील देश हैं
- दक्षिण - दक्षिणसहयोग के माध्यम से जुड़े हुये हैं

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- इसी अर्थव्यवस्था के संलग्न है
- NORMS के माध्यम से UNSC एवं अन्य ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की संरचना में परिवर्तन करना चाहते हैं
- औपनिवेशिक अतीत को साझा करते हैं अतः देशों की एकजुटता प्राप्त करते हैं
- विश्व में शांति स्थापना का बल देते हैं
- भारत द्वारा प्रायोजित BRICS एवं G-4 में सहभागी है।
- विभिन्न मंचों पर विकासशील देशों के मत का समर्थन करते हैं।

निष्कर्षतः भारत का लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध भारत के वैश्विक कद एवं नेतृत्व को बढ़ावा देने के सहायक हो सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. ऋण-जाल कूटनीति क्या है? चीन की ऋण-जाल कूटनीति भारत के पड़ोस में भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करती है?

What is debt-trap diplomacy? How does China's debt-trap diplomacy impact India's interests in its neighbourhood? (Answer in 150 words) 10

चीन की ऋण जाल कूटनीति किसी देश को ऋण प्रदान कर उसके देश पर नियंत्रण करने के माध्यम से जानी जा सकती है क्योंकि अल्पविकसित देश ऋण प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है जैसे- श्रीलंका

भारतीय हितों को ऋण जाल कूटनीति कैसे प्रभावित कर रही है

- हिंद महासागर में उपस्थिति जैसे श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिये लीज पर
- नेपाल में 40% FDI चाइना द्वारा निवेश के रूप में एवं ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- बांग्लादेश का BRI की तरफ झुकाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एवं चाइना के साथ संबंधो को बढ़ावा दिया जा रहा है

- पाकिस्तान में अब चाइना का अत्यधिक प्रभाव - ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन द्वारा किया जा रहा है। (चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से)
- मालदीव में चाइना द्वारा ऋण जाल की रणनीति के कारण मालदीव के द्वीपों में रणनीतिक की उपस्थिति भारत के लिए चिंता का मुद्दा है।
- भारत को घेरने के लिये चाइना ऋण जाल रणनीति का प्रयोग कर रहा है। जिसके तहत उच्च ब्याज दरों पर अत्यधिक ऋण दिया जा रहा है।

निष्कर्षतः, भारत को चाइना के विरुद्ध रणनीति के रूप में 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' के क्रियान्वयन को बेहतर किया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. विश्व भर के विभिन्न संविधानों का मिश्रण होने के बावजूद, भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता को आत्मसात किए हुए है। टिप्पणी कीजिए।

Despite being an amalgamation of various constitutions from across the world, the Indian Constitution imbibes social justice, pluralism, and equality through its various provisions. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 10 संविधानों (विदेशी) के प्रावधानों को देखा जा सकता है जिनके बारे में बी. आर. अंबेडकर ने कहा कि समकालीन समाज में समानताएँ अपेक्षित हैं।

भारतीय संविधान में विश्व भर के संविधानों के प्रावधान

① संसदीय शासन ब्रिटेन से

→ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है जहाँ भारत की द्विसदनीय विधायिका ब्रिटेन की भारत में शासन व्यवस्था के रूप में विकसित की गई

→ एकल नागरिकता को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है

② अमेरिका से

→ न्यायिक समीक्षा को प्रावधान लिया गया है

→ मूल अधिकारों का प्रावधान होना

→ उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है.

→ न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन

(3) कनाडा के संविधान से

→ अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र का अधिकार

→ केन्द्र का शक्तिशाली अर्थात् केंद्रीकरण को कनाडा से लिया गया है।

(4) आस्ट्रेलिया से

↳ व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता (अनु. -301)

(5) साउथ अफ्रीका

↳ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

(6) आयरलैंड

↳ राज्य के नीति निदेशक तत्वों को

(7) जापान

↳ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

(8) रूस

↳ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय.

(9) फ्रांस

↳ स्वतंत्रता समानता बंधुत्व

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(१०) (जर्मनी)
↳ आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन

(भारतीय संविधान के अपने प्रावधान)

- (सामाजिक न्याय) → भारत द्वारा नीति निदेशक तत्वों में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के
  39 (A) ⇒ निःशुल्क वैधानिक अधिकार का प्रावधान

- (बहुलवाद)
  ↳ प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष
  ↳ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)

- (समानता)
  ↳ अनुच्छेद 14, 15, 16 के माध्यम से समानता का अधिकार तो साथ ही समानों के साथ समान एवं असमानों के साथ असमान संरक्षण, आरक्षण के माध्यम से आवश्यकताओं के अनुसार परिस्थितियां

निष्कर्षतः भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो साथ ही भारत के संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है।

2086
VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. हाल के कुछ घटनाक्रमों ने भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे को प्रकाश में लाया है। देश में वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के लिए कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Recent developments have brought to light the issue of criminalizing marital rape in India. Analyse the implications of ensuring legal protection for victims of marital rape in the country. (Answer in 250 words) 15

भारत में वैवाहिक बलात्कार एक प्रमुख समस्या बनी हुई जिसे समाप्त करने के लिये न्यायिक एवं कानूनी उपाय आवश्यक है।

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे

सकारात्मक

- महिलाओं के जीवन के अधिकार को संरक्षण (अनुच्छेद - 21)
- लैंगिक सशक्तीकरण में सहायक
- समानता के अधिकार को बढ़ावा
- मानवअधिकारों के क्रियान्वयन में सहायक
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोका जा सकेगा।

2086
VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(नकारात्मक)

→ वैवाहिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव
→ सामाजिक तनाव बढ़ेगा
→ तलाक देने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है
→ संबंधों में गिरावट हो सकती है
→ विवाह जो भारत में एक संस्था माना गया है में गिरावट हो सकती है।

वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिये कानूनी संरक्षण

(सकारात्मक)

→ घरेलू हिंसा को रोका जा सकेगा
→ जीवन के अधिकारों की रक्षा संभव
→ सामाजिक समानता को सुनिश्चित किया जा सकेगा
→ समाज में हिंसा के प्रति कानूनी उपाय होने से कानूनी अधिकार उपलब्ध होगा
→ लैंगिक सशक्तीकरण में सहायक हो सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

नकारात्मक

- वैवाहिक संबंधों में अस्थिरता
- तलाक में वृद्धि हो सकती है
- सामाजिक समरसता भंग हो सकती है
- कानून का दुरुपयोग संभव हो सकता है
- 'फॉल्स केस' बढ़ सकते हैं।
- पारिवारिक संबंधों में गिरावट
- वाद-विवादों से न्यायिक बोझ बढ़ सकता है।

निष्कर्षतः वैवाहिक बलात्कार को नियंत्रित करने के लिये शिक्षा, जागरूकता एवं कानूनी उपाय सहायक हो सकते हैं तथा इन माध्यम से SDG-5 'जेंडर इक्वेलिटी' को प्राप्त किया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. "संघवाद के भारतीय मॉडल की अत्यधिक केंद्रीकृत होने के कारण आलोचना की जाती है, लेकिन यह राज्यों को पर्याप्त अवसर और स्वायत्तता भी प्रदान करता है।" विश्लेषण कीजिए।

"The Indian model of federalism has been criticized for being too centralized, but it also provides adequate space and autonomy to the states." Analyse. (Answer in 250 words) 15

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण वाद में कहा था कि भारतीय संघवाद प्रकृति में सहकारी संघवाद है।

संघवाद के केन्द्रीकृत ~~होने के कारण~~ विशेषताएँ

भारतीय संघवाद को अर्द्ध संघवाद कहा जाता है जिसमें केन्द्र अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है जैसे -

- केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
  - राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है (अनु. 153)
- राज्यपाल द्वारा विधानसभा के विधेयकों को आरक्षित रखना (अनु. 200)
- राष्ट्रपति शासन का प्रयोग (अनु. 356)
  - जिसमें राज्य की शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं
- समवर्ती सूची पर केन्द्र का अधिक नियंत्रण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को प्रदान (अनु. -248)
- राज्य सभा द्वारा 2/3 मतों के माध्यम से प्रस्ताव - फलतः राज्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र को (अनु. 249)
- सेस एवं अधिभार में वृद्धि
  - राज्यों को कम वित्त
- संविधान का संशोधन (अनु. 368)
- एकीकृत न्यायपालिका
- एकल नागरिकता आदि

राज्यों को पर्याप्त क्षमता एवं स्वायत्तता।

1. विधायी एवं सांविधानिक

- अनुच्छेद 279A - GST परिषद
- अनु.246 के तहत शक्तियों का विभाजन
- व्यापार-वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता (अनु. 301)
- अनु.280 के तहत वित्त आयोग के माध्यम से

विन्द का आवर्तन

→ उत्तर-पूर्वी परिषद एक्ट 1971 के माध्यम से राज्यों का विकास

→ विधानपरिषद का गठन (अनु. - 169)

→ क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना (राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से)

→ कार्यवाही

- नीति आयोग के माध्यम से राज्यों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- नीति आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देकर राज्यों को पर्याप्त अवसर दिये जा रहे हैं।

निष्कर्ष: भारतीय संघवाद भारतीय संविधान का आधारभूत ढाँचा है जिसे संविधान संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है (एस० आर० बोम्मई वाद)

14. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में नियुक्तियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय ने नियुक्ति प्रक्रिया को मूल रूप से बदल दिया है और इसके संभावित दूरगामी निहितार्थ भी हो सकते हैं। विवेचना कीजिए।

The recent judgment of the Supreme Court on appointments to the Election Commission of India (ECI) has fundamentally changed the appointment process and can have potentially far-reaching implications. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनु० 324 में उल्लेखित है जो भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

ECI में नियुक्ति को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने नियुक्ति प्रक्रिया को मूलरूप से बदला

- सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाने पर बल
- ECI की नियुक्ति में केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं
- ECI के अतिरिक्त अन्य कमिश्नरों की नियुक्ति के बारे में भी कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया जाये जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका की भागीदारी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

की शामिल होनी चाहिये

- ECI के नियुक्तियों को पारदर्शी बनाया जाना चाहिये
- राजनीतिक लाभ के लिये मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये
- राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये नियुक्तियों में पारदर्शिता लाया जाये

संभावित दूरगामी निहितार्थ

- निष्पक्ष नियुक्ति
  - ECI की क्षमता निर्माण में सहायक
  - दक्षता में वृद्धि कर सकती है
  - भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा
- लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना को बल मिलेगा एवं ECI इस माध्यम से सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रणाली को बिना पक्षपात को संचालित होगा

- नागरिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा
- सत्ताधारी पार्टी को अनावश्यक लाभ प्राप्त नहीं होगा
- निष्पक्ष नियुक्तियों से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा
  - ↳ क्योंकि कार्यपालिका स्वयं नियुक्ति करती है और स्वयं का निर्वाचन होता है।
- शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को बढ़ावा मिल सकेगा।

निष्कर्षतः निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिये निष्पक्ष नियुक्तियाँ आवश्यक है जिसके लिये स्पष्ट योग्यता एवं स्पष्ट प्रावधान अपरिहार्य हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. वैश्विक बदलावों के साथ समेकन और अर्थव्यवस्था के खुलने के परिणामस्वरूप लोक सेवाओं के लिए विविध चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण कुशल सेवा वितरण के लिए उनमें समग्र सुधारों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

Integration with the global trends and opening up of the economy has resulted in diversified challenges for the civil services, which require holistic reforms for efficient service delivery. Discuss. (Answer in 250 words) 15

वैश्विक बदलावों ने नवीन तकनीकियों को अपनाने पर बल दिया है जिसके कारण नवीन समस्याओं का जन्म हुआ है अतः इन समस्याओं से निपटने के लिये लोकसेवाओं में सुधार की आवश्यकता है।

लोक सेवाओं के लिये विविध-चुनौतियाँ

- ट्रिपिल इंपोसिबिलिटी (ट्रिलेमा)
  - इसके तहत (1) स्वतंत्र विदेश नीति
    (2) पूँजी का स्वतंत्र प्रवाह
    (3) विनिमय दर की स्थिरता

  इन तीनों का सामंजस्य 'इंपोसिबल ट्रिनिटी' कहलाता है अर्थात् एक साथ इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है.

- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण घरेलू प्राथिकों एवं बाह्य उत्तरदायित्वों

है बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है।

- नियमों एवं विनियमों का विश्व के साथ सामंजस्य के कारण कल्याणकारी कार्यों में बाधा - जैसे WTO के नियमों के अनुसार खाद्य सब्सिडी को लेने पर भारत की एक महत्वपूर्ण आबादी खाद्य संकट का सामना करेगी।

- एक देश की नीतियां दूसरे को प्रभावित जैसे अमेरिका द्वारा फेडरेट बढ़ने पर भारत से FDI निवेशक अपना पैसा निकालने लगते हैं।

- भूराजनीतिक प्रभाव
  - रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई में वृद्धि

कुशल सेवा वितरण के लिये सुधार

- वैदेशिक नीति को बेहतर एवं सुदृढ़
  - अमेरिका एवं रूस के साथ संबंधों में संतुलन
- खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये

WTO के बाम्सिफिकेशन की समाप्ति के लिये प्रयास

- PLI योजना के माध्यम से खाद्य एवं विनिर्माण पर बल
- आत्मनिर्भरता पहल के माध्यम सेवाओं को विस्तारित करना।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय समावेशन
- ई-श्रम खाता पारिस्थितिकी पर विचार विमर्श करते हुये आगे बढ़ना
- कॉमनी स्वैप स्मीकैर को बढ़ावा किया जा सकता है।
- व्यापारिक सुदृढ़ता को बढ़ावा जिसमे
  - → CEPA, FTA के माध्यम से संबंधो के गहराई

नवीन तकनीकियों जैसे AI, IOT, रोबोटिक्स एनालिटिक्स के माध्यम से लोक सेवा वितरण को बढ़ावा देकर सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को प्राप्त किया जा सकता है।

16. भारत में ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में ओपन डेटा क्या भूमिका निभा सकता है? देश में ओपन डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में कौन-सी चुनौतियां विद्यमान हैं?

What role can open data play in promoting transparency and accountability in e-governance in India? What are the challenges in ensuring the quality and reliability of open data in the country? (Answer in 250 words) 15

ई-गवर्नेंस वह अवधारणा है जिसमें विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से जवाबदेहिता, पारदर्शिता को शामिल कर शासन को कल्याणकारी बनाया जाये (UNDP)

ई-गवर्नेंस में ओपन डेटा की भूमिका

(i) पारदर्शिता बढ़ाने के लिये

- ओपन डेटा पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा जिसके माध्यम से 'लास्ट माइल तक पहुँच' सुनिश्चित होगी
- पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा
- समाज में असमानता में कमी आयेगी → भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135वें स्थान है

② जवाबदेहिता सुनिश्चित

→ नागरिक केन्द्रित शासन को बढ़ावा मिलेगा

→ राजनीतिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा

→ लोगों की शासन में सहभागिता में वृद्धि होगी

→ जवाबदेहिता को RTI Act, 2005 के माध्यम से ओपन डेटा के साथ जोड़ा जा सकता है।

→ यह ग्रासरूट डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगा

जैसे. ई-मित्र पोर्टल राजस्थान का

• CPGRAMS पोर्टल शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से जवाबदेहिता सुनिश्चित

→ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण

↳ लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट, 2013 के माध्यम से ओपन डेटा के साथ जोड़ने पर

P.T.O

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने में चुनौती

- फेक न्यूज के कारण कठिनाईयाँ
- डीप फेक एवं ~~ब्लैक~~ डार्क नेट की अवधारणा
- गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन
- सोशल मीडिया का बढ़ता प्रचलन और विस्तार
- सांस्कृतिक एवं सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है
- रचना एवं डेटा में परिवर्तन किया जा सकता है।
- साइबर अटैक

इन समस्याओं एवं चुनौतियों के समाधान के लिये तकनीकी संस्थानों को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसमें CERT-in एवं अन्य ऐसे साइबर सुरक्षा एवं समन्वय केंद्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. भारत में 'जीरो फूड' बच्चों की व्यापकता को कम करने के लिए मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

To reduce the prevalence of 'zero food' children in India, maternal nutrition needs to be made a priority. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत में 57% महिलायें एनीमिया रोग (NFHS-5) से ग्रसित हैं जो मातृ मृत्यु का भी एक कारण हैं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।

मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता क्यों?

- इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट (IMR) जो लगभग 35 है को कम करने के लिये आवश्यक है कि मातृ पोषण को सुधारा जाये।
- वेस्टिंग (कम वजन अनुपात) जो भारत में 35% है को कम करने के लिये मातृ पोषण आवश्यक है।
- स्टंटिंग को कम करने के लिये मातृ पोषण आवश्यक है।
- मालन्यूट्रिशन से निपटने के मातृ पोषण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवश्यक है।

- बच्चों के पोषण एवं उनको पोषणयुक्त भोजन देने के लिये मातृपोषण किया जाना एक बेहतर कदम हो सकता है।

- भारत में 16% आबादी कुपोषित (NFHS-5) को समाप्त करने के लिये सर्वोत्तम मातृपोषण आवश्यक है।

मातृपोषण

- ICDS के माध्यम से मातृपोषण के लिये न्यूट्रिशन बेस्ड फूड को बढ़ावा दिया जा रहा है
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मातृपोषण के लिये 6 महीने तक 6000 रुपये प्रति माह एवं मातृपोषण के लिये सुरक्षा
- NFSA, 2013 के माध्यम से मातृ पोषण पर बल दिया जा रहा है जहाँ महिला को मुखिया मानकर मोटा अनाज

एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

- पोषण अभियान के माध्यम से मातृपोषण पालन किया जा रहा है।
- पोषण प्लस स्ट्रैटजी को आगे अपनाये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- मातृ पोषण के साथ बच्चों के लिये न्यूट्रिशन बेल्ड भोजन
- टीकाकरण कार्यक्रम ICDS के माध्यम से
- आंगनवाड़ी के माध्यम से भोजन, दवाएं, टीकाकरण बढ़ावा एवं उसे और बेहतर क्रियान्वित किया जा सकता है।
- पोषण अभियान को मातृपोषण से जोड़ा जा सकता है।

मातृ पोषण जीरो हंगर (SDG-2) को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

2086

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. हाल ही में, केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी खाद्य सामग्रियों और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। भारत में लोक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंताएं क्या हैं? इनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है?

Recently, the Central government exempted all foods and drugs for rare diseases imported by people for personal use from customs duty. What are the concerns related to rare diseases as a public health issue in India? How can these be resolved? (Answer in 250 words) 15

स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है एवं वित्त आयोग ने स्वास्थ्य पर राज्यों को अपने GDP का 4% खर्च करने को कहा है अतः दुर्लभ रोगों के उपचार के लिये भाषा इंगित आवश्यक है

दुर्लभ रोगों के तहत

→ ऐसे रोगों को शामिल किया जाता है जिनकी उपचार आसानी से उपलब्ध नहीं होती है तो साथ ही समय के विकास के साथ इनके अन्य अनेक दुर्लभ रोगों का सामना करना पड़ सकता है।

दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंतायें

(1) आर्थिक — भारत में एक व्यक्ति स्वास्थ्य

पर लगभग 20-60% (अपनी आय का) खर्च करता है (Economic survey 2022-23)

→ भारत में 80% ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत शामिल नहीं है फलतः आर्थिक नुकसान और अत्यधिक हो जाता है।

(2) (बजट का आवंटन) (Economic survey)
↳ स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत अपनी GDP का 2.1% खर्च करता है जिससे दुर्लभ रोगों के बढ़ने से और बढ़ सकता है

(3) (सामाजिक)
↳ मानसिक तनाव में वृद्धि होगी है इस कारण (सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर) SUD बढ़ सकता है।
→ सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता

(4) दुर्लभ रोगों के कारण नवीन समस्याओं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

का जन्म हो सकता है जिसके
कारण विश्व एवं भारत में महामारी जैसी
समस्याएं जन्म ले सकती है।

समाधान

→ WHO की कार्य योजना के आधार पर राष्ट्रीय कार्य योजना को बढ़ावा

→ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के माध्यम से बजटीय आवंटन में वृद्धि को जेनव बनाया जा सकता है।

→ FSSAI के अभियान के रूप में 'ईट राइट इंडिया' को बढ़ावा

→ दुर्लभ रोगों के निदान में आयुष पद्धति अर्थात योग का इस्तेमाल किया जा सकता है।

निष्कर्षतः स्वास्थ्य क्षेत्र के अतिरिक्त GDP का 2% निवेश करने से 11 मिलियन रोजगार की प्राप्ति संभव है और SDG-1 नो पोवर्टी एवं SDG-3 good health and well being को प्राप्त करने में मददगार होगी है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए, इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करने और उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।
For realistic and effective collaborations to take place in the Indo-Pacific region, there is a need to acknowledge and recognize the underlining intention of the various countries with stakes in the region. Discuss. (Answer in 250 words) 15

हिंद-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में शक्तियों का प्रमुख केंद्र बिंदु बना हुआ है जहाँ भारत द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न मंचों एवं गठबंधनों के माध्यम से नेतृत्व भूमिका निभाई है जिसमें IPEF एवं FIPIC प्रमुख है।

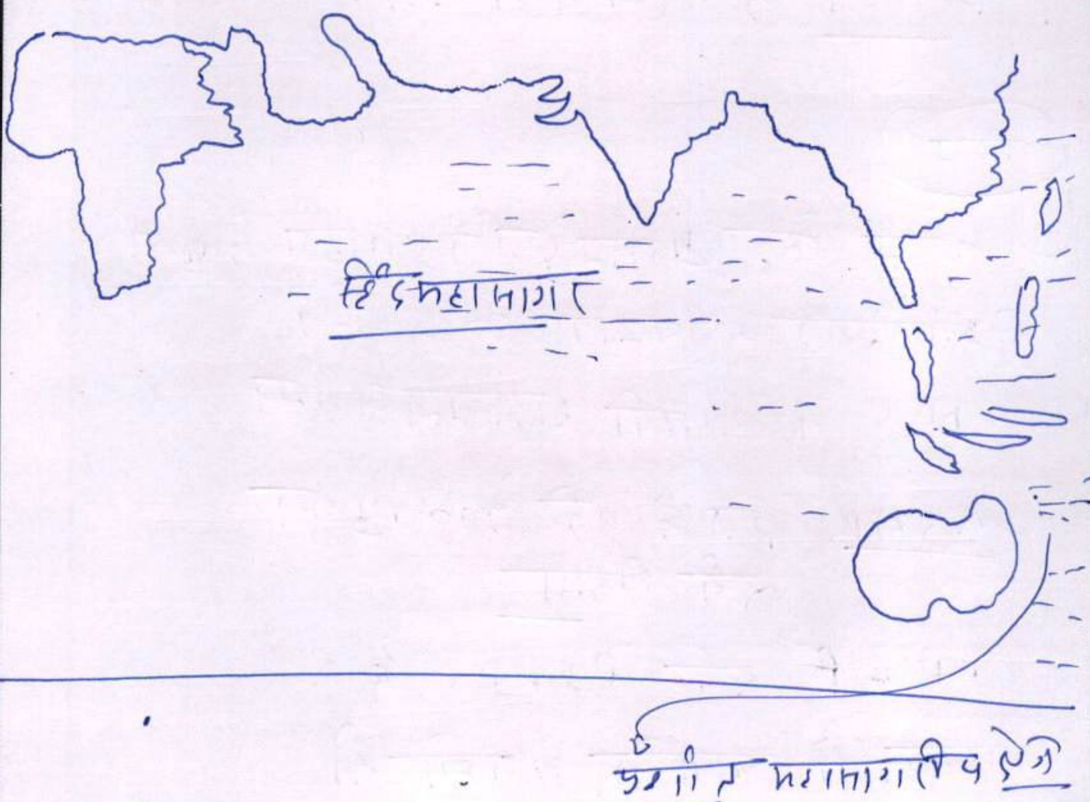

हिंद महासागर एवं प्रशांत क्षेत्र के यथार्थवादी

और प्रभावी सहयोग के लिये इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न देशों के प्रमुख हित एवं उनकी पहचान

① अमेरिका

- अमेरिका प्रशांत क्षेत्र एवं हिंद क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिये
- प्रशांत क्षेत्र के नौवहन स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये
  - यानी मेटलिक नाइस्यूज

यह → IPEF के माध्यम से जुड़ा है

② भारत

- भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के मध्य-मध्य को अपरेशन को बढ़ाया देने के लिये
- UNSC में स्थायी सदस्यता के लिये

→ SASAR क्षेत्र के शक्ति के लिये सुरक्षा एवं विकास

→ IPEF एवं FIPIC के माध्यम से व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे रहा है

(3) चाइना

→ अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को बढ़ावा देने के लिये

→ दक्षिण चीन सागर का नियंत्रण बनाये रखने के लिये

→ अपने व्यापार को सुरक्षित बनाये रखने के लिये

(4) जापान

→ जापान इस क्षेत्र में शांति स्थापना का सहयोग को बढ़ावा देने के लिये

(5) ~~[illegible]~~ ऑस्ट्रेलिया

→ आस्ट्रेलिया भी IPEF में शामिल है जो इस क्षेत्र को एक व्यापार मंच उपलब्ध कराएगा

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत द्वारा अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिये इस क्षेत्र से अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी को जोड़ना चाहिये।

20. भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थल के रूप में स्थापित होने से पहले, भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

There is a need to address the underlying challenges, both internal and external, in the North-Eastern region of India before it can serve as a pivotal connecting space between India and its neighbours. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत की पोरस बाउंड्री (छिद्रिल सीमा) तथा सामाजिक आर्थिक कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र को आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

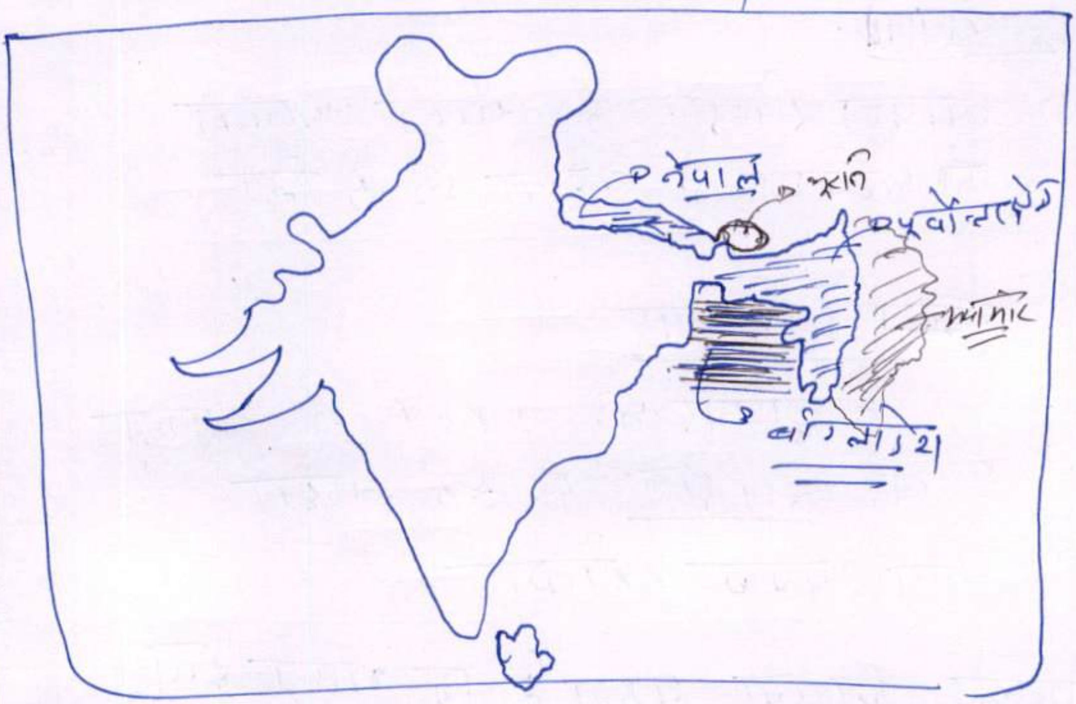

पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक चुनौतियाँ

- अलगाववाद

जिसके तहत अलग राज्य की मांग जैसे बोडोलैंड, ग्रेटर नागालिम

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- उग्रवाद
  - NSCN विद्रोही जैसे संगठन
  - काली ओगलांग क्षेत्र में उग्रवाद को बढ़ावा
- नृजातीय संघर्ष
  - मैइती एवं कुकी
    - जो हाल ही में मणिपुर में देखा गया
- आर्थिक एवं सामाजिक
  - आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र में आंतरिक संघर्ष एवं हिंसात्मक संगठनों के रूप को बढ़ावा मिलता है

बाह्य चुनौतियाँ

→ संगठित अपराध
- मादक पदार्थों की तस्करी
- मनी लांड्रिंग

→ शरणार्थी संकट → अवैध प्रवास जैसे -

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी लोगों का अवैध प्रवास

समाधान

→ कनेक्टिविटी
- ↳ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से
- → भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग
- ↳ अखौरा-अगरतला रेलवे लिंक

→ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत
- ↳ PM-DEVINE योजना के तहत इसका विकासीय अवसंरचना
- → उड़ान 4.0 के माध्यम से हवाई मार्गों का उपयोग

→ शांति समझौतों को अपनाया जा रहा है।

→ BOLD QIT योजना

→ CIBMS के तहत नवीन तकनीकियों का उपयोग

2nd ARC ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भावनात्मक संबंधों को बढ़ावा देने का बल दिया है।